

NT>

Title: Need to stop privatisation of nationalized banks.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के सभी बैंकों के 30 हजार से अधिक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन का मेन मुद्दा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। जैसे कि सदन को मालूम है कि 12 लाख 40 हजार करोड़ रुपया बैंकों का टोटल डिपोजिट है, इसमें से जो 70 प्रतिशत डिपोजिट है वह साधारण लोगों का, आम गरीब लोगों का है। यदि प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, प्राइवेट बैंकों की क्या हालत है, लोगों को मालूम है। उनके पैसे की सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है - एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट की हो, जो गरीबी उन्मूलन की है, ये सारे के सारे उससे प्रभावित होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन का है। अभी जो भी पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर हैं, वहां रिजर्वेशन लागू है। प्राइवेट सेक्टर में जो जा रहा है, उसमें से रिजर्वेशन खत्म होता जा रहा है। अभी तक 37 हजार करोड़ रुपए की सम्पत्ति बेची जा चुकी है, उसमें से कम से कम एस सी और बैकवर्ड क्लासेस का 50 प्रतिशत, यानि करीब 19 हजार करोड़ रुपए उनका हिस्सा बनता है। दूसरी जाति में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एम्प्लायमेंट जेनरेशन का कोई कार्यक्रम चले तब तो बात समझ में आती है। एक तरफ लोग अनएम्प्लायड हो रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें जो हिस्सा मिलता था, वे बेच कर दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका सबसे बुरा प्रभाव आरक्षित वर्ग के लोगों पर ही पड़ने वाला है। **श्री** (व्यवधान) जैसा कि सदन को मालूम है कि 19 राष्ट्रियकृत बैंक हैं और ये सारे के सारे मुनाफे में चल रहे हैं।

अभी भी 8108 करोड़ रुपया बैंकों को फायदा हुआ है। बड़े लोगों के पास 83 हजार करोड़ रुपया बकाया लोन है। अगर वह वसूल किया जो तो बैंकों को प्राइवेट हाथों में जाने का कोई कारण नहीं बनता है। आज बैंक कर्मचारी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बिल सरकार ने पेश किया है और जिसमें 33 प्रतिशत इक्विटी का मामला लाया गया है, हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसे वापस करें और जो आरक्षित श्रेणी के लोगों के हितों पर इससे कुठाराघात होने वाला है, उसको रोकने का काम करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, हमारा भी इस पर नोटिस है।

MR. SPEAKER: I have received the notices for Tehelka Commission Inquiry from several Members. On this we are going to take a decision. So, during discussion, Members can raise it. This cannot be a matter of Adjournment Motion.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, मैं आपको टाइम दूंगा। मुझे तो सभी को पर्मिशन देनी है। आप लोगों को पर्मिशन दिये बिना कैसे काम चलेगा? ममता जी, आप बोलिये।